

Letter No. 1144/Personnel-2-2001-53(1)/2001

Rakesh Sharma
Secretary
Government of Uttarakhand

All Principal Secretaries/Secretaries/Additional Secretaries
Government of Uttarakhand

All District Magistrates
Uttarakhand

All Head of Departments
Uttarakhand

Dehradun Date: 18 July 2001

Subject: For reservation in State Services, Educational Institutes and Public Industries, Corporations and Autonomous Institutes


In context to above, I am directed to say that after proper consideration of the policy for reservation in state public industries/corporations, autonomous institutes/ educational institutes, Government has decided to opt to increase one percent reservation on the basis of the available census. Therefore, government has decided to apply following provisional reservation in Uttarakhand State:

- | | |
|---------|-----|
| (1) SC | 19% |
| (2) ST | 04% |
| (3) OBC | 14% |

Government has also decided to give horizontal reservation to Women, Ex-army person, PWD and Freedom fighters and their dependents in the following manner:

- | | |
|---|-----|
| (1) women | 20% |
| (2) Ex Army Person | 02% |
| (3) PWD | 03% |
| (4) Freedom fighters and their dependents | 02% |

Horizontal reservation will be allowed into the respective categories.
Permanent policy for reservation will be determined separately.


PRINCIPAL

Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

Sincerely
Rakesh Sharma
Secretary

श.क. शर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

विषय

देहरादून दिनांक 18 जुलाई, 2001

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सार्वजनिक उद्यमों/निगमों स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने में सम्यक् रूप से विचारीपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़ों उपलब्ध होने तक, वर्तमान जनसंख्या (सेगिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनुपात निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

(1) अनुसूचित जाति	19%
(2) अनुसूचित जनजाति	04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्रामियों के आश्रितों का निम्नानुसार हॉरिजेंटल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :-

(1) महिलाएं	20%
(2) भूतपूर्व सैनिक	02%
(3) विकलांग व्यक्ति	03%
(4) स्वतंत्रता संग्राम संग्रामियों के आश्रित	02%

होने/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेंटल आरक्षण अनुमन्य होगा।

शासन के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक् से किया जायेगा।

भवदीय,
श.क. शर्मा,
सचिव।

सख्या 1144 (1)/कामिक-2-2001-53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विद्यान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव माननीय मन्त्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
आर० सी० लोहन्
अनु सचिव।

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

Letter No. 1900/XXX(2)/26(a)

From
Nrip Singh Napchayal
Principal Secretary
Government of Uttaranchal

- To
1. Additional Chief Secretary
Government of Uttaranchal
 2. All Principal Secretaries/ Secretaries
Government of Uttaranchal
 3. All HODs/Office Head
Uttaranchal
 4. Divisional Commissioner Garhwal/Kumayun
Uttaranchal
 5. All District Magistrate
Uttaranchal

Personnel Division -2

Dehradun Date 24 July 2006

Subject: Allowing horizontal reservation to women in State services/corporation/public sector and autonomous Institutes of Uttaranchal

Dear Sir

In context to above, I am directed to say that according to G.O. Letter No. 1144/Personnel-2-2001-53(1)/2001, Dated: 18 July 2001, Para 2 (i), 30 % reservation is allowed to women of Uttaranchal State.

In this context, after proper consideration by Government it is decided to increase women horizontal reservation from 20% to 30% in state services/corporation/public sector and autonomous Institutes of Uttaranchal. This 30% reservation will not be implemented in those issues, where selection process has already been started and advertised. Any old issues will not be entertained.


Kindly grant horizontal reservation to Uttaranchal women accordingly.

Sincerely
Nrip Singh Napchayal
Principal Secretary

No. 1966/XXX(2)/2006

Copy to:

1. Principal Secretary, Hon Governor, Uttaranchal Government
2. Secretary, Public Service Commission, Uttaranchal, Haridwar
3. Registrar, High Court, Uttaranchal Nanital
4. Secretary, Legislative Assembly, Uttaranchal Dehradun
5. All personnel secretaries of Hon Ministers
6. All divisions of Secretariat


PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

- 1. नृप सिंह नवलख्यान
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।
- 2. अपर प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।
- 3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
- 4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयप्रमुख
उत्तरांचल।
- 5. मण्डलाध्यक्ष महानगर/कुशीमुं
उत्तरांचल।
- 6. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

30/-
1000/XXX

कार्यिक अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 24 जुलाई 2006

विषय उत्तरांचल की राज्यधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को शैक्षणिक आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनसदर संख्या 1000/कार्यिक-2-2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 के प्रसंग 2 (i) द्वारा उत्तरांचल राज्य की महिलाओं को 20 प्रतिशत शैक्षणिक आरक्षण प्रदान किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समस्त विधायकसभ उत्तरांचल राज्य की राज्यधीन सेवाओं निगमों सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिए वर्तमान शैक्षणिक आरक्षण 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 30 प्रतिशत शैक्षणिक आरक्षण तब लागू नहीं होगा जब तक प्रत्येक प्रारम्भ हो गयी हो और विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो। और कोई पुराने प्रकरण पुनर्जांचावित नहीं होंगे।

3. कृपया उपरोक्तानुसार उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिये शैक्षणिक आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
नृप सिंह नवलख्यान
प्रमुख सचिव।

संख्या 1000/XXX(2)/2006

संबन्धी विभागाध्यक्ष को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

- 1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
- 2. सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
- 3. विचलक राज्य न्यायालय, उत्तरांचल मैथिलाल।
- 4. सचिव विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।
- 5. समस्त सचिवों के निजी सचिव को मां० भवदीयों के सूचनाएं।
- 6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 7. विभागीय आदेश-पुस्तिका।

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Daknathar, Vikasnagar

आज्ञा से
रोशन चन्द लोहनी
समुक्त सचिव

संख्या- 1022-(1)/XXIV(4)/2019-01(03)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव/प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग), उत्तराखण्ड द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।
11. एन.आई.सी (निदेशक), सचिवालय परिसर, देहरादून।

PRINCIPAL

Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

आज्ञा से,

(डॉ० अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

F.No.20013/01/2018-BC-II

Government of India

Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment

17th January, 2019

Shastri Bhawan, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions.

In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

- i. 5 acres of Agricultural Land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

[Handwritten signature]
17/1/19

iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/ UT.

4. Every Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority, increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, are not less than the total seats available in the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

5. Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DoPT and Ministry of HRD respectively.


(B.L. Meena)

Joint Secretary to the Government of India

To

1. The Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi
2. The Secretary, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi



F No: 12-4/2019-U1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 17th January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) for admission in Central Educational Institutions.

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, it has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten per cent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

- a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institutions, (as defined in clause (d) of section (2) of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.
- b) The above reservation would not be applicable to the 8 institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.
- c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of

[Handwritten Signature]
17/1/19

study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

- d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.
- e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

4. This issues with the approval of the Minister for Human Resource Development.

Encl: As above


(Smita Srivastava)
Director

1. Chairman UGC
2. Chairman AICTE
3. Chairperson NCTE
4. All Bureau Heads of Department of Higher Education

Copy to:

Chief Secretaries of all State Governments/UTs: with a request to give effect to the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 for all higher educational institutions funded/aided, directly or indirectly, by the State Government in such manner that the provision for reservation for EWS would become operational from the academic year 2019-20.

SCHEDULE

(The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006)

S.No.	Names of the Institutions of Excellence, etc.
1.	Homi Bhabha National Institute, Mumbai and its constituent units, namely:- <ol style="list-style-type: none">(i) Bhabha Atomic Research Centre, Trombay;(ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam;(iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore;(iv) Institute for Plasma Research, Gandhinagar;(v) Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata;(vi) Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata;(vii) Institute of Physics, Bhubaneswar;(viii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai;(ix) Harish-Chandra Research Institute, Allahabad;(x) Tata Memorial Centre, Mumbai.
2.	Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
3.	North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Shillong.
4.	National Brain Research Centre, Manesar, Gurgaon.
5.	Jawaharaj Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
6.	Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
7.	Space Physics Laboratory, Thiruvananthapuram.
8.	Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun.

12/1/19

Form No. 1

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family**' is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
attested photograph of
the applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

G. Srinivasan